INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 11 | DECEMBER – 2025

"रीवा जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर डिजिटल भुगतान प्रणाली का प्रभाव : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन"

डॉ. सुनील कुमार
अतिथि विद्वान, व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग,
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.).

सारांश –

वर्तमान समय में डिजिटल भुगतान प्रणाली आधुनिक आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक बन चुकी है, जिसने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत ही गहराई से प्रभावित किया है। विशेष रूप से नोटबंदी, डिजिटल इंडिया अभियान, जन–धन योजना, यूपीआई, भीम एप, मोबाइल बैंकिंग तथा आधार आधारित भुगतान प्रणालियों के प्रसार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लेन–देन के पारंपरिक स्वरूप को सर्वाधिक परिवर्तित किया है। रीवा जिला, जो मुख्यतः कृषि एवं ग्रामीण आजीविका पर आधारित है, ऐसे क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन हेतु एक उपयुक्त क्षेत्र प्रदान करता है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य रीवा जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर डिजिटल भुगतान प्रणाली के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट किया गया है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली ने लेन–देन को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। यद्यपि तकनीकी साक्षरता, नेटवर्क समस्या एवं साइबर सुरक्षा आदि समस्याएं चुनौतियाँ भी सामने बनी हुयी है, फिर भी डिजिटल भुगतान प्रणाली दीर्घकाल में ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए एक सशक्त माध्यम बन सकती है।

मुख्य शब्द : डिजिटल भुगतान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वित्तीय समावेशन, रीवा जिला, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग आदि।

प्रस्तावना –

21वीं सदी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की संरचना को व्यापक रूप से परिवर्तित किया है। भारत जैसे विकासशील देशों में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहकर आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक विस्तारित हो रहा है। वर्तमान डिजिटल भुगतान प्रणाली इसी तकनीकी परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जिसने पारंपरिक नकद आधारित लेन–देन प्रणाली को सरल बनाया है।

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक रूप से नकद आधारित रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित बैंकिंग सुविधाएँ, कम साक्षरता दर तथा तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण डिजिटल लेन–देन का विस्तार अपेक्षाकृत धीमा रहा है। परंतु वर्ष 2016 के बाद नोटबंदी, डिजिटल इंडिया अभियान और शासकीय प्रोत्साहन योजनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को अपनाने की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है।

रीवा जिला मध्यप्रदेश का एक प्रमुख कृषि प्रधान जिला है, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी निवास करती है। जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, लघु व्यापार एवं दैनिक मजदूरी पर आधारित है। ऐसे में डिजिटल भुगतान प्रणाली का प्रभाव केवल आर्थिक लेन–देन तक सीमित न रहकर आय, उपभोग, बचत तथा निवेश व्यवहार आदि को भी सशक्त रूप में प्रभावित करता है।

आधुनिक समय में डिजिटल भुगतान प्रणालियों– यूपीआई, भीम एप, मोबाइल वॉलेट, एटीएम कार्ड, आधार आधारित भुगतान एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रही है। इससे बिचौलियों की भूमिका में कमी आयी है, सरकारी लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचते हैं तथा पारदर्शिता में वृद्धि होती है। इसके साथ–साथ ग्रामीण उपभोक्ताओं की बाजार तक पहुँच भी सुदृढ़ हुयी है।

यद्यपि डिजिटल भुगतान प्रणाली के समक्ष कई व्यवधान भी हैं। जिनमें तकनीकी साक्षरता का अभाव, इंटरनेट नेटवर्क की अस्थिरता, साइबर अपराध का भय तथा पारंपरिक नकद लेन–देन की आदतें आदि इसके व्यापक प्रसार में बाधक हैं। रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन व्यवधानों का स्वरूप और प्रभाव समझना इस शोध का मुख्य आधार रहा है।

इस प्रकार प्रस्तुत शोध पत्र रीवा जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान प्रणाली की भूमिका, प्रभाव एवं संभावनाओं का अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है।

शोध का उद्देश्य –

आधुनिक समय में डिजिटल भुगतान प्रणाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन का माध्यम बन रही है। रीवा जिले जैसे कृषि प्रधान क्षेत्र में इसके प्रभाव का अध्ययन नीति–निर्माण एवं स्थानीय आर्थिक विकास की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। इस शोध का उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणाली के आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करना है। अतः प्रस्तुत शोध पत्र से संबंधित उद्देश्यों का विवरण निम्नानुसार है –

(1) रीवा जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान प्रणाली के उपयोग की स्थिति का अध्ययन करना।
(2) डिजिटल भुगतान प्रणाली का ग्रामीण उपभोक्ताओं, किसानों एवं व्यापारियों की आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव का विश्लेषण करना।
(3) अध्ययन क्षेत्र में डिजिटल भुगतान से संबंधित समस्याओं एवं संभावनाओं की पहचान करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को केन्द्र में रखकर प्रस्तुत शोध पत्र को समाज विज्ञान के मानकों के अनुरूप पूर्ण किया गया है।

शोध विधि –

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आँककों का संकलन रीवा जिले के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों से 300 उत्तरदाताओं से संरचित प्रश्नावली एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से किया गया है। इन उत्तरदाताओं में किसान, ग्रामीण व्यापारी, श्रमिक एवं उपभोक्ता शामिल किये गये हैं।

द्वितीयक आँकड़े विभिन्न सरकारी रिपोर्टों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, जनगणना रिपोर्ट, शोध पत्रों, पुस्तकों एवं विश्वसनीय पत्र–पत्रिकाओं से प्राप्त किए गए हैं। संकलित आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, तुलनात्मक एवं वर्णनात्मक पद्धति द्वारा किया गया है। शोध कार्य में अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी गई है, जो समाज विज्ञान संकाय का एक प्रमुख आयाम है और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ में मानी जाती है।

विश्लेषण –

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश उत्तरदाताओं ने सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशि, कृषि उत्पादों की बिक्री तथा दैनिक खरीद–फरोख्त में डिजिटल माध्यमों का प्रयोग किया है। जिनके भुगतान हेतु यूपीआई एवं मोबाइल बैंकिंग सर्वाधिक प्रचलित माध्यम पाये गये। शोध क्षेत्र में डिजिटल भुगतान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह में कमी तथा लेन–देन की पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। किसानों को फसल भुगतान

सीधे बैंक खातों में प्राप्त होने से बिचौलियों पर निर्भरता कम हुई है। ग्रामीण व्यापारियों के लिए भी डिजिटल भुगतान ने व्यवसाय को औपचारिक स्वरूप प्रदान किया है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि तकनीकी जानकारी की कमी, नेटवर्क समस्या तथा साइबर सुरक्षा का भय डिजिटल भुगतान को अपनाने में प्रमुख बाधाएँ बनी हुयी हैं। इसके बावजूद युवा वर्ग एवं शिक्षित ग्रामीणों में डिजिटल भुगतान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखा गया और वे अपने प्रत्येक भुगतान की प्रक्रिया में डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, जिससे भुगतान संबंधी प्रक्रिया आसान हुयी हैं। इस प्रकार उनकी वास्तविकता का आकलन करने के लिए प्राथमिक स्तर पर अध्ययन क्षेत्र से चयनित किये गये उत्तरदाताओं से समंकों का संकलन किया गया है, जिनका विवरण इस प्रकार है –

सारणी क्रमांक 01
ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान उपयोग की प्रस्थिति

क्रमांक	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	नियमित रूप से डिजिटल भुगतान करने वाले	135	45.00
2.	कभी–कभी डिजिटल भुगतान करने वाले	90	30.00
3.	बहुत कम डिजिटल भुगतान करने वाले	45	15.00
4.	डिजिटल भुगतान न करने वाले	30	10.00
	कुल योग	3000	100.00

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित।

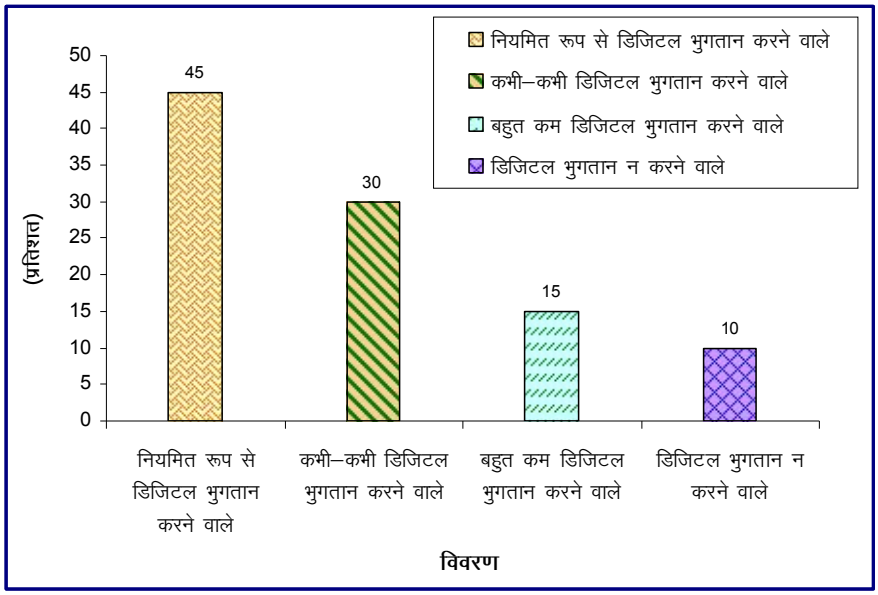

आरेख क्र. 01 : ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान उपयोग की प्रस्थिति

उपरोक्त सारणी के समंकों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 45 प्रतिशत उत्तरदाता नियमित रूप से डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग करते हैं, जो डिजिटल जागरूकता में वृद्धि को दर्शाता है। जबकि 30 प्रतिशत उत्तरदाता कभी–कभी डिजिटल भुगतान का प्रयोग करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे संक्रमण काल में हैं। 15 प्रतिशत उत्तरदाता बहुत कम डिजिटल भुगतान करते हैं, जबकि 10 प्रतिशत उत्तरदाता अभी भी पूरी तरह नकद आधारित लेन–देन पर निर्भर हैं। अतः यह स्थिति दर्शाती है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, किंतु पूर्ण स्वीकृति हेतु अभी प्रयास आवश्यक हैं।

निष्कर्ष –

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली ने रीवा जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है, लेन–देन में पारदर्शिता आई है तथा ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को औपचारिक स्वरूप प्राप्त हुआ है। किसानों, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान सुविधा, सुरक्षा एवं समय की बचत का माध्यम बना है।तकनीकी साक्षरता, नेटवर्क सुविधा एवं साइबर सुरक्षा से संबंधित समस्याएँ अभी भी मौजूद हैं। यदि सरकार एवं बैंकिंग संस्थाएँ प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता एवं अवसंरचना पर ध्यान दें, तो डिजिटल भुगतान प्रणाली ग्रामीण विकास का सशक्त उपकरण सिद्ध हो सकती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी शहरी नागरिकों की भांति डिजिटल लेन–देन को बढ़ाया जा रहा है जिससे सम्पूण अर्थव्यवस्था को कौशलेश अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद मिलेगी।

संदर्भ –

1. भारतीय रिजर्व बैंक, डिजिटल भुगतान पर रिपोर्ट, मुंबई, 2019।
2. नाबार्ड, ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन, नई दिल्ली, 2020।
3. भारत सरकार, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम रिपोर्ट, नई दिल्ली, 2021।
4. टोडारो, एम. पी., आर्थिक विकास, पियरसन प्रकाशन, लंदन, 2018।
5. मिश्रा, एस. के., भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुंबई, 2019।
6. भारत की जनगणना, प्राथमिक जनगणना सार, 2011।
7. विश्व बैंक, विकास हेतु डिजिटल अर्थव्यवस्था, वाशिंगटन डी.सी., 2020।